"हम वर्ष 2022 में स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक नए संसद भवन में अपना सत्र आयोजित करेंगे": लोक सभा अध्यक्ष

कैंप ओटावा, 8 जनवरी 2020: राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 25 वें सम्मेलन में बोलते हुए लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला ने कहा कि हमारे संसद भवन के गौरवशाली 92 वर्ष पूरे हो गए हैं; इसका निर्माण वर्ष 1927 में किया गया था। इस बात का उल्लेख करते हुए कि अपने बढ़ते जनादेश के साथ संसद के दायित्व भी बढ़ गए हैं, श्री बिरला ने कहा कि 'नए भारत' के निर्माण के सपने को साकार करने के लिए संसद भवन में संसद सदस्यों तथा अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पर्याप्त स्थान और सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है । उन्होंने प्रतिनिधियों को इस बात की जानकारी भी दी कि भारत वर्ष 2022 में अपनी स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक नए संसद भवन में अपना सत्र आयोजित करेगा। साथ ही, उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैले सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास का कार्य आरंभ कर दिया गया है और इस पुनर्विकास कार्य का लक्ष्य कम से कम 250 वर्षों की भावी आवश्यकताओं को पूरा करना है।

श्री बिरला ने कहा कि संसद भवन की वास्तुकला किसी देश और देशवासियों की आकांक्षाओं का प्रतीक होती है; यह राष्ट्र के स्वरूप, उसकी परंपराओं तथा सांस्कृतिक विरासत का भी मूर्त रूप होती है । उन्होंने कहा कि विधिनिर्माताओं की बढ़ती संख्या और संसदों के बढ़ते हुए कार्य के परिणामस्वरूप, पूरे विश्व में विधानमंडलों का विस्तार हो रहा है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि संसद भवनों के नवीकरण और पुनर्निर्माण से संसदों की सांस्कृतिक, तकनीकी और संरचना में ऐसे बदलाव करने के अवसर मिलते हैं जिससे नागरिकों को अपनी संसदों से जुड़ने और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सहायता मिलती है।

श्री बिरला ने कहा कि पूरे विश्व में विधानमंडलों को संसदीय भवनों के नवीकरण और उनके पुनरूद्धार के बारे में विचार करना पड़ा ताकि संसदों को 21 वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके। उन्होंने यह विचार व्यक्त किया

कि कम से कम पूंजी तथा संसदीय कार्यों में बिना किसी व्यवधान के साथ कम से कम समय-सीमा में नवीकरण और पुनर्निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए सदस्यों और स्टाफ की राय लिया जाना महत्वपूर्ण है। इस संबंध में उन्होंने इस बात का उल्लेख भी किया कि भारत की संसद ने नए संसद भवन की रूपरेखा को अंतिम रूप देते समय सभी संबंधित व्यक्तियों की राय ली है और नए संसद भवन के निर्माण के समय उनके सुझावों पर अमल भी किया जायेगा।

राज्य सभा के उप सभापति, श्री हरिवंश ने **"संसदीय गतिविधियां : स्पष्टता, पारदर्शिता और जवाबदेही"** विषय पर अपने विचार रखते हुए कहा कि संसदों का जनता के साथ संवाद एक जीवंत लोकतान्त्रिक प्रणाली का आधार है और यह आवश्यक है कि संसदों की भूमिका और कार्यों के साथ साथ सभाओं में होने वाले कार्यों की जानकारी लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाई जाए ।

श्री हरिवंश ने इस बात पर भी बल दिया कि स्पष्टता, पारदर्शिता और जवाबदेही एक सफल संसदीय लोकतन्त्र का आधार हैं। इस बात का उल्लेख करते हुए कि ये तीनों परस्पर जुड़े हुए हैं और एक-दूसरे को बल प्रदान करते हैं, श्री हरिवंश ने कहा कि ये मूलत: उस विश्वास तथा भरोसे की नींव पर खड़े होते हैं, जो जनता अपने प्रतिनिधियों पर करती है जिनसे विधानमंडल का निर्माण होता है। अत: विधानमंडलों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने कार्यकरण के विभिन्न स्तरों पर नागरिकों के साथ जुड़ें और निरंतर जुड़ते रहें ।